भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 206

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

ई-विद्या और डिजिटल कक्षाएं

206 श्रीमती भारती पारधी:

डॉ. भोला सिंह:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीएम ई-विद्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के साथ-साथ असम के आदिवासी और पहाड़ी जिलों, जिनमें कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ शामिल हैं, में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है;

(ख) देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले और असम में, पीएम ई-विद्या और दीक्षा, ई-पाठशाला और डिजिटल कक्षाओं जैसी डिजिटल और स्मार्ट शिक्षा पहलों के कार्यान्वयन की प्रगति/स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) कवर किए गए ग्रामीण जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट, स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट या डिजिटल बोर्ड जैसी डिजिटल अवसंरचना से सुसज्जित सरकारी स्कूलों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, ताकि डिजिटल शिक्षा संसाधनों और ऑनलाइन शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसी डिजिटल शिक्षण पहलों में पहुँच, प्रभावशीलता या उपयोग अंतराल के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(च) क्या सरकार का मानना है कि सभी जिलों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े जिलों में, पर्याप्त बुनियादी शिक्षा अवसंरचना उपलब्ध है और यदि नहीं, तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) सभी जिलों में "दीक्षा" और "स्वयं" प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण और सामग्री वितरण की स्थिति क्या है और बुलंदशहर जिले सहित ब्लॉक-वार कार्यरत सरकारी स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), जो एक परिवर्तनकारी नीति है, इस बात पर बल देती है कि कुछ विषयों, कौशल और क्षमताओं को सभी छात्रों द्वारा सीखा जाना चाहिए जिसमें डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल सोच शामिल है, जिन्हें विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में **पीएम ई-विद्या** नामक एक व्यापक पहल दिनांक 17 मई, 2020 को शुरू की गई, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों सहित देश भर में शिक्षा तक बहु-विध पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पीएम ई-विद्या पहल को समग्र शिक्षा योजना के तहत आवंटित बजट के माध्यम से समर्थन प्राप्त है और इसे एनसीईआरटी के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। इन पहलों के घटक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों के उपयोग, निगरानी और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहकार्यता करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है।

पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटक भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में अनुकूलित हैं और इसमें शामिल हैं:

- **200 डीटीएच टीवी चैनल:** इन चैनलों का शुभारंभ दिनांक 9 मार्च 2024 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को 200 पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। एनसीईआरटी के साथ समझौता ज्ञापन के तहत यह चैनल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों को आवंटित किए गए हैं और प्रचालनरत हैं, विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	आवंटित चैनल
1	असम	डीडी एएस पीएम ईविद्या 58 से डीडी एएस पीएम ईविद्या 62
2	मध्य प्रदेश	डीडी एमपी पीएम ईविद्या 108 से डीडी एमपी पीएम ईविद्या 112
3	महाराष्ट्र	डीडी एमएच पीएम ईविद्या 113 से डीडी एमएच पीएम ईविद्या 117
4	उत्तर प्रदेश	डीडी यूपी पीएम ईविद्या 173 से डीडी यूपी पीएम ईविद्या 177

इसके अलावा, 6 दिसंबर, 2024 को, भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप और आईएसएल में शिक्षण-अध्यापन सामग्री की व्यापक

पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, माननीय शिक्षा मंत्री ने एक समर्पित पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल (अध्याय संख्या 31) के माध्यम से श्रवण बाधित समुदाय के लिए सुलभ शिक्षण संसाधनों के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक समर्पित पहल शुरू की। दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डेज़ी) पर और एनसीईआरटी/एनआईओएस वेबसाइट तथा यूट्यूब चैनलों पर सांकेतिक भाषा में विशेष ई-सामग्री तैयार की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा डीटीएच चैनलों और यूट्यूब पर प्रतिदिन डिजिटल साक्षरता पर एक घंटे की सामग्री प्रसारित की जाती है।

- **दीक्षा:** ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्र का डिजिटल अवसंरचना है **(एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म)**। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म पर कंप्यूटर विज्ञान के पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता घटक शामिल हैं।

राज्य का नाम	पंजीकृत उपयोगकर्ता	अधिगम सत्र	अधिगम मिनट	ई-सामग्री
असम	3.44 लाख	7.81 करोड़	74.53 करोड़	11,478
मध्य प्रदेश	9.97 लाख	54.05 करोड़	30.82 करोड़	5,751
महाराष्ट्र	10.12 लाख	775.55 करोड़	331.88 करोड़	22,640
उत्तर प्रदेश	25.97 लाख	103.45 करोड़	1405.27 करोड़	16,974

एनईपी 2020 की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, 117 भारतीय भाषा प्राइमर जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य युवा शिक्षार्थियों और वयस्कों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिसमें तमिल के लिए एक प्राइमर भी शामिल है।

महत्वपूर्ण आलोचनात्मक विचार कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता के लिए स्थान हेतु, **300** से अधिक वर्चुअल लैब बनाए गए हैं और उन्हें दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण:** शिक्षा मंत्रालय (एमओई) स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल शिक्षा स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को लागू कर रहा है। निष्ठा पाठ्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक, एफएलएन, ईसीसीई और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए डिजाइन और संचालित किए गए हैं। निष्ठा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर रूप से निर्मित ई-सामग्री का उपयोग करके ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाते हैं। निष्ठा

(प्राथमिक, माध्यमिक, एफएलएन और ईसीसीई) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों सहित लगभग **65** लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। निष्ठा संभवतः भारत के स्तर पर दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। एनसीईआरटी कक्षा ग्यारहवीं से बारहवीं के लिए स्वयं पोर्टल के माध्यम से **11** विषयों को शामिल करते हुए 28 पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। चौदह चक्र पूरे हो चुके हैं और लगभग 4,90,952 शिक्षार्थी लाभान्वित हुए हैं। बुलंदशहर जिले सहित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जिलावार गणना यूडाइज+ पोर्टल (https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications) से प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय, तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहलों को लागू करता है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन पहलों के अंतर्गत, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकता के अनुसार आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई जाती है। आईसीटी योजना दो विकल्प प्रदान करती है:

1. **विकल्प I:** जिन स्कूलों के पास पहले से आईसीटी सुविधाएँ नहीं हैं, वे आईसीटी लैब या स्मार्ट कक्षाएं चुन सकते हैं। 700 से ज़्यादा छात्रों वाले स्कूलों को एक अतिरिक्त आईसीटी लैब मिल सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप और प्रशिक्षण संसाधन, डिजिटल बोर्ड की सहायता, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनल खरीद सकते हैं।
2. **विकल्प II:** मौजूदा आईसीटी सुविधाओं वाले स्कूल योजना के मानदंडों के तहत स्मार्ट कक्षाओं या टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार प्रतिवर्ष यूडाईज रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो डिजिटल शिक्षण उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और संबंधित बुनियादी ढांचे तक पहुंच के बारे में आंकड़े प्रदान करता है। यूडाइज+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के 3,51,734 स्कूलों में से 75,375 स्कूलों में आईसीटी लैब, 1,00,599 स्कूलों में टैबलेट, 34,848 स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, 1,29,655 स्कूलों में डिजिटल बोर्ड/स्मार्ट बोर्ड/वर्चुअल क्लासरूम/स्मार्ट टीवी के साथ स्मार्ट क्लासरूम और 1,83,630 स्कूलों में इंटरनेट सुविधाएं हैं। विस्तृत रिपोर्ट यूडाइज+ पोर्टल **(https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications)** से प्राप्त की जा सकती है।

****